भारतीय जनता पार्टी

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी का वक्तव्य

नई दिल्ली – 16 सितम्बर, 2008

आन्ध्रपदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा वोट–बैंक राजनीति के चलते हैदराबाद मुक्ति दिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाने से इनकार

कल हैदराबाद मुक्ति दिवस की 60वीं वर्षगांठ है। मैं उन शहीदों और देशभक्तों को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने भूतपूर्व हैदराबाद राज्य जो निजाम के दमनकारी शासन के अधीन था, की मुक्ति के लिए संघर्ष किया।

17 सितम्बर 1948 का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वास्तव में एक निर्णायक मोड़ था। हैदराबाद की जनता की सामूहिक इच्छा–शक्ति ने न केवल इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश बनाने हेतु निजाम के प्रयासों को निष्फल कर दिया बल्कि इस प्रांत को भारत संघ में मिलाने का भी निश्चय किया। जब 15 अगस्त, 1947 को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो निजाम के राजसी शासन के लोग हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाने की मांग करने पर अत्याचार और दमन का सामना कर रहे थे। हैदराबाद की जनता ने निजाम और उसकी निजी सेना 'रजाकारों' की क्रूरता से निडर होकर अपनी आजादी के लिए पूरे जोश से लड़ाई जारी रखी।

भारत के भूतपूर्व गृहमंत्री एवं 'लौह पुरूष' सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा पुलिस कार्रवाई करने हेतु लिए गए साहसिक निर्णय ने निजाम को 17 सितम्बर, 1948 को आत्म–समर्पण करने और भारत संघ में सम्मिलित होने पर मजबूर कर दिया। इसलिए शेष भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद हैदराबाद की जनता को अपनी आजादी के लिए 13 महीने और 2 दिन संघर्ष करना पड़ा था। **यदि निजाम को उसके षड़यंत्र में सफल होने दिया जाता तो भारत का नक्शा वह नहीं होता जो आज है।**

इसलिए, अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए भूतपूर्व हैदराबाद की जनता की मांग पूर्णतः उचित है। कर्नाटक और महाराष्ट्र जिन्हें भूतपूर्व निजाम राज्य के दो हिस्से मिले थे, की सरकारों ने स्वतंत्रता आन्दोलन को पूरी तरह अभिस्वीकृति दी है। इसके परिणामस्वरूप, कर्नाटक और महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों में 17 सितम्बर का दिन हर वर्ष हैदराबाद राज्य मुक्ति दिवस के रूप में सरकारी तौर पर मनाया जाता है।

दुर्भाग्य की बात है कि आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र की जनता 17 सितम्बर को निजाम शासन से मिली अपनी आजादी का सरकारी तौर पर जश्न मनाने से वंचित है। वर्ष 1998 में हैदराबाद मुक्ति दिवस की स्वर्ण–जयंती समारोह के दौरान इस मांग में तेजी आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितम्बर, 1998 को एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया था जिसमें मैंने केन्द्रीय गृहमंत्री की हैसियत से हिस्सा लिया था। इसके बाद ही 17 सितम्बर को वार्षिक समारोह के रूप में मनाने की मांग तेलंगाना में एक बार फिर से मुखरित हुई है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आन्ध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शासक दल की वोट–बैंक नीति के चलते इस मांग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। मुझे ऐसी कोई शंका नजर नहीं आती कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को सरकारी तौर पर मनाये जाने से किसी समुदाय की भावनाएं आहत होंगी। बहरहाल, तेलंगाना मुक्ति संघर्ष इस बात का साक्षी है कि शोयबुल्ला खां जिन्हें मारने से पहले उनके हाथों को काट दिया गया था, ने ही वास्तव में मुक्ति आंदोलन की ज्वाला भड़काई थी।

17 सितम्बर को सरकारी मान्यता देने की मांग एक अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है जिसका भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है।

मैं चाहूंगा कि केन्द्र और राज्य सरकारें यह महसूस करें कि तेलंगाना के लोगों के लिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना तब तक अधूरा रहेगा जब तक उन्हें 17 सितम्बर को अपना मुक्ति दिवस मनाये जाने की अनुमति नहीं दी जाती। **मैं भारत और आन्ध्र प्रदेश की सभी देशभक्त ताकतों से आग्रह करता हूं कि वे तेलंगाना के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का समर्थन करें।**

–*–*–*–*–